The six demands of the Union are as follows:—

(1) Implementation of the recommendations of—

(i) Workshops Committee;

(ii) Stores Committee; and

(iii) Uniforms Committee.

(2) Revision of pay scales of—

(i) M. T. Drivers; and

(ii) Telephone Operators.

(3) Reduction in duty hours of Chowkidars.

(4) (i) Revision of overtime rates; and

(ii) Grant of nine effective holidays for operational staff.

(5) Promotion to the extent of 50% to non-gazetted supervisory posts, purely on seniority basis; and

(6) Creation of posts of Senior Clerks/Head Clerks/Superintendents, on the basis of yardsticks prevailing in other Departments like Income-tax, P. & T. etc.

Decisions have already been reached and communicated to the Union in respect of their demands Nos. 1(ii) & (iii), 2(i) & (ii) 3, 4(i) & (ii) and 5; the remaining demands, *viz.* Nos. 1(i) and 6 have far reaching implications and are under examination.

Sugar Mills in Bihar

2566. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have urged the Centre for establishing some Co-operative Sugar Mills in the State of Bihar; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy): (a) Yes, Sir.

The Government of Bihar have sponsored 11 applications for the establishment of new cooperative sugar factories.

(b) The applications received from Bihar will be considered along with applications from other states when the next batch of new sugar factories is taken up for licensing. The applications are under examination.

भू-राजस्व की वसूली

2567. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कृषकों को, जिनसे 1954 में भू-राजस्व नहीं लिया गया था, कहा गया जा रहा है कि वे ग्यारह वर्ष का सारा भू-राजस्व एक साथ जमा करायें ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह भू-राजस्व आसान किश्तों में लेने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) तथा (ख) भूमि राजस्व लेना कभी बन्द नहीं किया था । परन्तु यह सच है कि दिल्ली के संघ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार प्राकृतिक प्रकोप जसा कि बाढ़, तथा जलमगनता इत्यादि के कारण भूमि राजस्व की वसूली कई वर्षों तक स्थगित रखी गई । इस अच्छी फसल के कारण कृषकों की वित्तीय दशा में सुधार हुआ है । अतः पिछली जुलाई में वसूली करने का विशेष कार्य शुरू किया गया था । परन्तु किसी भी बाकीदार को बकाया राशि एक साथ देने पर आबद्ध

नस्हीं किया गया। इस बात पर हर ध्यान दिया गया कि किसी को इस से विशेष कठिनाई न हो।

(ग) जैसा कि प्रश्न के (क) तथा (ख) भाग के उत्तर में कहा गया है कि यह सब वसूलियां किसी कठिनाईयां दिये बिना की जा रही हैं। सच तो यह है कि बहुदा वसूलियां बकाया राशि के भाग से ही की गई हैं। जहां आवश्यक होगा शेष राशि आसान किश्तों में भी वसूल की जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतलें

2568. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बाल्मीकी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना अब इसके द्वारा बनाई गई दूध की खाली बोतलों को लेने से इन्कार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाली बोतलों की कीमत बढ़ा दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आहमदाब खां): (क) दिल्ली दूग्ध योजना कोई दुध की बोतलें नहीं बनाती है। योजना यह बोतलें बाजार से खरीदती है और कार्ड वालों को बेचती है। उन व्यक्तियों के लाभ के लिये जो दिल्ली छोड़ जायें या दिल्ली दुग्ध योजना से दुध लेना बन्द कर दें, बोतलों को वापस योजना को बेचने का प्रबन्ध किया था। इस प्रबन्ध से केन्द्रीय डेरी से खाली बोतलें चोरी होने लग गई। तथा वे बोतलें दिल्ली दुग्ध योजना के डीपुओं में बिकने लग गई। इस कारण यह प्रबन्ध बन्द कर दिया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Exclusion of Some Tribes from List of Scheduled Tribes

2569. **Shri Raghunath Singh:** Will the Minister of **Social Security** be pleased to state:

(a) how many States have suggested to the Centre to exclude some tribes or castes from the list of Scheduled Tribes as they are fairly developed and has no distinctive tribal traits; and

(b) if so, the details of such suggestions and action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shrimati Chandrasekhar): (a) and (b). The whole question of revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was placed before the Advisory Committee for revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes constituted by Government. The Report of the Committee is under consideration.

Mogul Lines Limited, Bombay

2570. **Shri Narendra Singh Mahida:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to take over private shares of Mogul Lines Limited, Bombay and merge it with the Shipping Corporation of India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, reasons therefore?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is not considered feasible due to commercial as well as administrative considerations, to merge Mogul Lines Limited with the Shipping Cor-